शनिवार, 6 जून, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

रजत पाटीदार को इंडिया ए में जगह मिलने की संभावना

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

रणवीर सिंह को मिली राहत, 'डॉन 3' विवाद में FWICE ने वापस लिया फैसला

Page-05

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मजाक उड़ाने वाले देश की प्रगति नहीं समझते। उन्होंने दावा किया कि जनता कांग्रेस को लगातार नकार रही है और भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।

'निराशावादियों से सावधान' : सूरत में पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के सूरत में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में कुछ निराशावादी लोग लगातार 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान का मजाक उड़ाते हैं और राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण संकल्प को कमतर आंकने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे लोग भूल जाते हैं कि जो देश दूसरों पर निर्भर रहता है, वह कभी भी विकास और प्रगति की उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता, जिनका वह वास्तव में हकदार है। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के सपनों और संकल्पों का प्रतीक है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लंबे समय तक देश को दूसरे देशों पर निर्भर बनाए रखा, जबकि वर्तमान सरकार भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर राजनीतिक हमला जारी रखते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों से पार्टी अराजकता और अनिश्चितता के माहौल में अवसर तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन देश की जनता ने हर बार उसे करारा जवाब दिया है।

- आत्मनिर्भर भारत पर सवाल उठाने वालों पर पीएम मोदी का हमला।
- जनता कांग्रेस की राजनीति को लगातार नकार रही है: मोदी।

उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता ने कांग्रेस को पहले ही हाशिये पर पहुंचा दिया है और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां भी जनता उसके शासन से निराश है। उन्होंने हाल ही में हुए हिमाचल प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार होने के बावजूद पार्टी को वहां हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन राज्यों की जनता ने भी कांग्रेस को स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी राजनीति अब स्वीकार्य नहीं है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने वैश्विक चुनौतियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दुनिया इस समय अभूतपूर्व संकटों के दौर से गुजर रही है। कोविड-19 महामारी, विभिन्न क्षेत्रों में युद्ध, ऊर्जा संकट और पेट्रोल-गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। इसके बावजूद भारत ने मजबूती से इन चुनौतियों का सामना किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब नकारात्मक सोच से आगे बढ़ चुका है और आशावाद, आकांक्षाओं तथा दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि जब किसी राष्ट्र की सामूहिक इच्छाशक्ति मजबूत होती है, तो वह किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है।

रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब और तेज दौड़ेंगी एक्सप्रेस ट्रेनें

देश भर के लाखों रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि भारतीय रेलवे सैकड़ों मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की गति में उल्लेखनीय वृद्धि करने की तैयारी कर रहा है। खबरों के अनुसार, रेलवे बोर्ड ने एक महत्वाकांक्षी योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य भारत के प्रमुख मार्गों पर कई लंबी दूरी की ट्रेनों की अधिकतम गति को 110 किमी प्रति घंटे से बढ़ाकर 130 किमी प्रति घंटे करना है। इस कदम से यात्रियों के लिए रेल यात्रा तेज, अधिक कुशल और अधिक आरामदायक होने की उम्मीद है, जिससे नियमित मेल और एक्सप्रेस सेवाएं राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों के मानकों के करीब पहुंच जाएंगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, प्रस्तावित उन्नयन के अंतर्गत लगभग 350 से 400 लंबी दूरी की मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें शामिल होने की संभावना है। यह योजना मुख्य रूप से उन ट्रेनों पर केंद्रित होगी जिनमें पहले से ही आधुनिक एलएचबी कोच लगे हुए हैं। जर्मन तकनीक पर आधारित ये कोच 160 किमी प्रति घंटे तक की गति से सुरक्षित रूप से चलने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे आवश्यक बुनियादी ढांचा उन्नयन पूरा होने के बाद ये उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त हो जाते हैं। इस पहल से देश भर में लंबी दूरी की यात्रा के लिए पारंपरिक ट्रेन सेवाओं पर निर्भर रहने वाले यात्रियों के एक बड़े वर्ग को लाभ मिलने की उम्मीद है।

पुतिन का दावा: BRICS ने आर्थिक ताकत में G7 को पछाड़ा, दुनिया की धुरी बदल रही है

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि ब्रिक्स समूह आर्थिक आकार के मामले में जी7 को पहले ही पीछे छोड़ चुका है और आने वाले वर्षों में और भी आगे बढ़ने की संभावना है। इंडिया टुडे द्वारा संचालित सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच (एसपीआईईएफ) में बोलते हुए पुतिन ने कहा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि विकास की संरचना धीरे-धीरे वैश्विक दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो रही है। पुतिन का ब्रिक्स समूह को कड़ा समर्थन ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इस समूह के खिलाफ जमकर बोल रहे हैं। इस समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। बाद में मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात भी इस समूह में शामिल हो गए। पिछले साल, ट्रम्प ने ब्रिक्स को अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बताया था और इस पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। अपने संबोधन में रूसी राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि विकास की संरचना नए विकास केंद्रों और वैश्विक दक्षिण के देशों के पक्ष में बदल रही है। इसी संदर्भ में उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि ब्रिक्स देश नए विकास केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। पुतिन ने कहा कि अगर आप पिछले पांच वर्षों के वैश्विक जीडीपी पर नजर डालें, तो आप पाएंगे कि इसकी वार्षिक वृद्धि का लगभग आधा हिस्सा - 49% - ब्रिक्स देशों का है। तथाकथित जी7 का योगदान लगभग 18% अनुमानित है। उन्होंने विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में ब्रिक्स देशों के लिए काफी तेज विकास दर का भी अनुमान लगाया।

CBSE पोर्टल पर साइबर हमला, बोर्ड ने दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

सीबीएसई ने अपने पोस्ट-रिजल्ट सर्विसेज पोर्टल पर समन्वित साइबर हमलों के संबंध में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सीबीएसई ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि 24×7 निगरानी के माध्यम से सभी हमलों को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर लिया गया, और किसी भी प्रकार का डेटा लीक या सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। इस बीच, सीबीएसई के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर कुल 70,433 सफल आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें अंकों के सत्यापन के लिए 7,314 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,119 आवेदन शामिल हैं। सीबीएसई ने बताया कि 3 जून 2026 को लगभग 38 लाख पैकेटों के दुर्भाविनापूर्ण डिनायल-ऑफ-सर्विस (DoS) हमले के बावजूद, तकनीकी टीमों के समय पर हस्तक्षेप के कारण पोर्टल सुरक्षित और चालू रहा। समाचार एजेंसी एएनआई ने यह जानकारी दी है। सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जून की मध्यरात्रि है। कई छात्रों ने सोशल मीडिया हैंडल X के माध्यम से पुनर्मूल्यांकन/सत्यापन के लिए आवेदन करने में आ रही समस्याओं के बारे में चिंता व्यक्त की है। बोर्ड ने सोशल मीडिया पर अपनी चिंताएं साझा करने वाले छात्रों को जवाब देते हुए कहा, "कृपया अपनी चिंता डीएम के माध्यम से साझा करें। सीबीएसई टीम आपकी सहायता करेगी।" उम्मीदवार सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन के लिए आधिकारिक वेबसाइट - cbse.gov.in/newsite_old/rchk.html पर आवेदन कर सकते हैं।

पटना फायरिंग केस में बड़ा मोड़, खान सर के खिलाफ मामला दर्ज

पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुई गोलीबारी की घटना में एक नया घटनाक्रम सामने आया है। पुलिस ने खान सर की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। उनके खिलाफ पटना के कदमकुआं पुलिस स्टेशन में फायरिंग और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई उनके कोचिंग सेंटर से हुई गोलीबारी का वीडियो सामने आने के बाद की गई है। खान सर का कहना है कि गोलीबारी आत्मरक्षा में की गई थी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें एफआईआर की जानकारी नहीं है और वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि गार्डों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी और उनकी टीम इस मामले की जांच करेगी। खान सर के कोचिंग सेंटर पर पत्थरबाजी की घटना पर एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने कहा कि वीडियो में फायरिंग करते दिख रहे दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया है और गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके हथियार जब्त कर लिए गए हैं और जांच के लिए एफएसएल (FSL) को भेज दिए गए हैं। जांच के दौरान जो भी सबूत सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह कानून व्यवस्था से संबंधित हो या आपराधिक मामलों से। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षक खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पटना के कदमकुआं पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 109 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25(9), 27 और 35 के तहत शिक्षक खान सर सहित तीन नामजद व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जब खान सर के संस्थान से जुड़े दो गार्डों को 2 जून की घटना के एक वीडियो के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कथित तौर पर दो लोगों को गोली चलाते हुए दिखाया गया था। खबरों के मुताबिक, कोचिंग सेंटर में हुई गोलीबारी और हंगामे, वायरल वीडियो और जांच में मिले सबूतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

बिहार चुनाव का बिगुल, BJP-JDU ने उतारे अपने उम्मीदवार

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को 2026 के बिहार विधानसभा द्विवार्षिक चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पार्टी ने आगामी चुनावों के लिए भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह, डॉ. संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं, जनता दल (यूनाइटेड) ने शुक्रवार को 2026 बिहार विधानसभा द्विवार्षिक चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। पार्टी ने बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना के माध्यम से उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी की। इस घोषणा के साथ, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी ने विधानसभा चुनावों के लिए अपनी तैयारियों की औपचारिक शुरुआत कर दी है, साथ ही सामाजिक प्रतिनिधित्व और संगठनात्मक शक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करने का संकेत भी दिया है। विधानसभा की खाली सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए जेडीयू ने शेखपुरा निवासी ललन प्रसाद पर भरोसा जताया है। पार्टी नेतृत्व ने उन्हें उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस खाली सीट के लिए होने वाले मुकाबले पर राजनीतिक जगत का काफी ध्यान जाने की उम्मीद है, खासकर तब जब पार्टियां अपनी चुनावी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुट गई हैं। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद, जेडीयू ने राज्य भर में अपने चुनाव अभियान की तैयारियों को तेज कर दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठनात्मक इकाइयों को उम्मीदवारों का सक्रिय रूप से समर्थन करने और जमीनी स्तर पर जनसंपर्क प्रयासों को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर कोरिया दौरे पर जाएंगे शी चिनफिंग

एशिया की राजनीति में बढ़ेगी हलचल

लगभग सात वर्षों के अंतराल के बाद चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग उत्तर कोरिया की यात्रा पर जा रहे हैं।यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब उत्तर कोरिया और रूस के बीच रणनीतिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। विशेषज्ञ इसे पूर्वी एशिया में बदलते शक्ति संतुलन और चीन की क्षेत्रीय भूमिका को मजबूत करने की महत्वपूर्ण पहल मान रहे हैं।

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग 8 जून से उत्तर कोरिया की दो दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। लगभग सात वर्षों बाद होने वाली यह यात्रा अंतरराष्ट्रीय राजनीति और पूर्वी एशिया के सामरिक परिदृश्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस दौरे को केवल एक द्विपक्षीय यात्रा के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, सुरक्षा चिंताओं और बदलते वैश्विक गठबंधनों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करना है। चीन लंबे समय से उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा आर्थिक और राजनीतिक सहयोगी रहा है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कोरोना महामारी के कारण दोनों देशों के बीच संपर्क सीमित हो गया था। सीमाएं बंद होने से व्यापार और लोगों की आवाजाही पर भी असर पड़ा था। अब जब दोनों देशों ने धीरे-धीरे परिवहन और व्यापारिक गतिविधियों को बहाल करना शुरू किया है, तब यह उच्चस्तरीय यात्रा संबंधों में नई ऊर्जा भरने का प्रयास मानी जा रही है।विशेषज्ञों के अनुसार इस यात्रा के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण उत्तर कोरिया और रूस के बीच बढ़ती निकटता भी है। यूक्रेन युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया द्वारा रूस को समर्थन दिए जाने के बाद दोनों देशों के संबंधों में उल्लेखनीय मजबूती आई है। रूस और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ते सैन्य तथा रणनीतिक सहयोग ने चीन को भी सतर्क कर दिया है। बीजिंग नहीं चाहता कि उसका पारंपरिक सहयोगी पूरी तरह मॉस्को के प्रभाव में चला जाए। इसलिए चीन इस यात्रा के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि प्योंगयांग का सबसे महत्वपूर्ण और भरोसेमंद साझेदार अब भी चीन ही है।दौरे के दौरान दोनों नेताओं के बीच सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, सीमा व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति तथा क्षेत्रीय स्थिरता जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति भी बातचीत के प्रमुख मुद्दों में शामिल हो सकते हैं। चीन लगातार यह प्रयास करता रहा है कि कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव नियंत्रित रहे और किसी बड़े सैन्य टकराव की स्थिति न बने।इस यात्रा पर अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया की भी विशेष नजर बनी हुई है। उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षणों और परमाणु कार्यक्रम को लेकर पहले से ही क्षेत्र में तनाव मौजूद है। ऐसे में चीन की सक्रिय कूटनीति आने वाले समय में क्षेत्रीय समीकरणों को प्रभावित कर सकती है।कुल मिलाकर, शी चिनफिंग की यह यात्रा केवल चीन और उत्तर कोरिया के संबंधों तक सीमित नहीं है। यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक राजनीति, महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा और भविष्य के कूटनीतिक संतुलन को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण घटना साबित हो सकती है। दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषक इस दौरे के परिणामों पर करीबी नजर बनाए हुए हैं।

फीफा विश्व कप 2026 से पहले सुरक्षा तैयारियां तेज, तीन देशों में हाई अलर्ट

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों में शामिल फीफा विश्व कप 2026 के शुभारंभ से पहले अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में व्यापक सुरक्षा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 11 जून से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट को लेकर तीनों देशों की सरकारें किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक से बचने के लिए विशेष रणनीति पर काम कर रही हैं। अधिकारियों ने इसे विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ा सुरक्षा अभियान बताया है।इस बार विश्व कप का आयोजन पहली बार तीन देशों की संयुक्त मेजबानी में हो रहा है। प्रतियोगिता में 48 टीमें भाग लेंगी और 16 विभिन्न शहरों में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। बड़ी संख्या में खिलाड़ियों, अधिकारियों और लाखों दर्शकों के आने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां विशेष सतर्कता बरत रही हैं।आयोजकों के अनुसार स्टेडियमों, प्रशिक्षण केंद्रों, टीम होटलों, हवाई अड्डों और फैन जोन की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। साइबर सुरक्षा को भी विशेष प्राथमिकता दी गई है ताकि टिकटिंग, प्रसारण और डिजिटल नेटवर्क पर किसी प्रकार का हमला न हो सके। ड्रोन निगरानी और ड्रोन-रोधी प्रणालियों की भी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि तीनों देशों की खुफिया एजेंसियां लगातार सूचनाओं का आदान-प्रदान कर रही हैं। संभावित आतंकवादी खतरों, साइबर हमलों और भीड़ प्रबंधन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त कमांड सेंटर स्थापित किए गए हैं। हजारों पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मी और आपदा प्रबंधन दल आयोजन स्थलों पर तैनात रहेंगे।विश्व कप केवल खेल आयोजन नहीं बल्कि वैश्विक स्तर का सांस्कृतिक और आर्थिक कार्यक्रम भी माना जाता है। ऐसे में इसकी सफलता और सुरक्षा सुनिश्चित करना मेजबान देशों की सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया है।

अन्नामलाई ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

बीजेपी से इस्तीफे देने वाले के. अन्नामलाई ने शुक्रवार को नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। अन्नामलाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने भविष्य के प्लान के बारे में बताया। अन्नामलई ने कहा कि मैंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। आज से एक नए सफर की शुरुआत होगी। एक नए पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत करूंगा। आप सबको मेरा साथ देना है। अन्नामलाई ने कहा कि मैं साफ सुथरी पॉलिटिक्स की शुरुआत करना चाहता हूं। जब दल बन जाएगा तो टर्म लिमिट लेकर आएंगे ताकि परिवार वाद वाली राजनीति पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि मेरा राजनीतिक सफर आसान नहीं था। DMDK में 2009 में इंटर्नशिप किया। 2020 में बीजेपी जॉइन किया और आज नए सफर की शुरुआत कर रहा हूं। 24 अगस्त 2020 को जब बीजेपी ज्वाइन करने जा रहा था। तब रजनीकांत ने मुझे फोन किया और कहा कि उनकी पार्टी में ज्वाइन करूं। उस समय बीएल संतोष को वादा कर चुका था। इसीलिए रजनीकांत को मना कर दिया और बीजेपी में शामिल हो गया। अन्नामलई ने कहा कि हम अपनी पार्टी के सिद्धांत और नीतियों का एलान बाद में करेंगे। पीएम मोदी के प्रति मेरे मन में हमेशा आदर रहेगा लेकिन बीजेपी से अगर किसी मुद्दे पर हमारा मतभेद है तो उसे पूरी गंभीरता के साथ उठाया जाएगा। 3 लैंगुएज पॉलिसी का विरोध मैंने बीजेपी के अंदर रहते हुए विरोध किया था। पूर्व आईपीएस ने कहा कि अमित शाह को स्पष्टीकरण दिया कि मैं तमिलनाडु में बैठकर इस्तीफा भेजने वालों में नहीं हूं। इसीलिए उनसे मिलकर जो भी कमी मुझे लगी उनको बताया और इस्तीफा किया। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने शुक्रवार को अन्नामलाई का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इसके साथ ही अन्नामलाई और बीजेपी की राहें छह साल बाद जुदा हो गई।

वैश्विक आर्थिक विकास दर का अनुमान घटा बढ़ती तेल कीमतों ने बढ़ाई चिंता

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर एक बार फिर चिंताजनक संकेत सामने आए हैं। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने वर्ष 2026 के लिए वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 2.4 प्रतिशत कर दिया है। एजेंसी का कहना है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, ऊर्जा संकट और कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतों का विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।रिपोर्ट के अनुसार हाल के महीनों में तेल उत्पादक क्षेत्रों में अस्थिरता बढ़ने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। इसका सीधा असर परिवहन, विनिर्माण और ऊर्जा क्षेत्र पर पड़ रहा है। तेल महंगा होने से उत्पादन लागत बढ़ रही है, जिसके कारण दुनिया के कई देशों में महंगाई फिर से बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है।फिच रेटिंग्स ने चेतावनी दी है कि यदि तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं तो अमेरिका, यूरोप और एशिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर प्रभावित हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति घटने और निवेश में कमी आने से वैश्विक मांग कमजोर पड़ सकती है। इसका असर अंतरराष्ट्रीय व्यापार और रोजगार के अवसरों पर भी दिखाई दे सकता है।विशेषज्ञों का मानना है कि विकसित देशों के केंद्रीय बैंकों के सामने भी नई चुनौती खड़ी हो गई है। यदि महंगाई बढ़ती है तो ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा बनाए रखना पड़ सकता है, जिससे आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार और धीमी हो सकती है। दूसरी ओर विकासशील देशों पर विदेशी निवेश और मुद्रा विनिमय दरों का दबाव बढ़ सकता है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तकनीक और हरित ऊर्जा क्षेत्रों में बढ़ता निवेश कुछ अर्थव्यवस्थाओं को सहारा दे सकता है। इसके बावजूद निकट भविष्य में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि दुनिया को आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और संतुलित नीतियों की आवश्यकता होगी।

एल-नीनो की आशंका से एशिया में बढ़ी चिंता, सूखा और बाढ़ का खतरा

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

विश्व मौसम विज्ञान विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि वर्ष 2026 के दूसरे भाग में एल-नीनो प्रभाव विकसित होने की संभावना काफी बढ़ गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके कारण एशिया के अनेक देशों में मौसम का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे कहीं भीषण गर्मी और सूखे की स्थिति उत्पन्न होगी तो कहीं अत्यधिक वर्षा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ जाएगा।मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार एल-नीनो प्रशांत महासागर के जल तापमान में होने वाला एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जिसका प्रभाव पूरी दुनिया के मौसम चक्र पर पड़ता है। एशियाई देशों में इसका सबसे अधिक असर कृषि, जल संसाधनों और खाद्य सुरक्षा पर देखने को मिलता है। भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों में वर्षा की कमी होने की आशंका व्यक्त की गई है। इससे खेती-किसानी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और किसानों की चिंता बढ़ सकती है।विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में मानसून सामान्य से कमजोर रह सकता है। यदि ऐसा होता है तो धान, दाल और अन्य प्रमुख फसलों का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। दूसरी ओर चीन और जापान के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना जताई गई है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है।संयुक्त राष्ट्र से जुड़े जलवायु विशेषज्ञों ने सरकारों को पहले से तैयारी करने की सलाह दी है। जल संरक्षण, आपदा प्रबंधन और कृषि योजनाओं को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण एल-नीनो जैसी घटनाओं का प्रभाव पहले की तुलना में अधिक गंभीर हो सकता है।दुनिया भर के मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। यदि आगामी महीनों में एल-नीनो पूरी तरह सक्रिय होता है तो इसका असर वैश्विक खाद्य बाजार, ऊर्जा मांग और आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि एशिया के कई देशों ने अभी से एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

संपादक की कलम से

लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित व्यवस्था नहीं है। इसकी असली ताकत जनता के उस भरोसे में छिपी होती है कि उसका मत स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रभावी है। जब चुनावों की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं, तब मामला केवल किसी दल की जीत या हार का नहीं रहता, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता भी बहस के केंद्र में आ जाती है। हाल के दिनों में चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठे आरोपों ने इसी चिंता को फिर सामने ला दिया है। यह कहा जा रहा है कि कई बार केवल कुछ सीटों का परिणाम ही नहीं, बल्कि पूरी सत्ता का स्वरूप भी चुनावी प्रक्रियाओं से प्रभावित हो सकता है। मतदाता सूचियों में गड़बड़ी, मतदान के दौरान कथित अनियमितताएं और संस्थागत निष्पक्षता पर उठते सवाल लोकतंत्र के लिए चिंताजनक संकेत हैं। यदि जनता को यह महसूस होने लगे कि उसका मत पूरी ईमानदारी से दर्ज नहीं हो रहा, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव कमजोर पड़ने लगती है। भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग माना जाता है। करोड़ों मतदाता हर चुनाव में उत्साह से भाग लेते हैं और इसी भागीदारी से लोकतंत्र को शक्ति मिलती है। लेकिन यही शक्ति तब कमज़ोर होने लगती है जब चुनावी प्रक्रिया को लेकर संदेह पैदा होता है। संदेह चाहे वास्तविक हो या केवल राजनीतिक विवाद का हिस्सा, उसका असर आम नागरिक के मन पर पड़ता है। मतदाता के मन में यदि यह सवाल पैदा हो जाए कि उसका मत सही अर्थों में गिना भी जाएगा या नहीं, तो यह स्थिति किसी भी लोकतंत्र के लिए गंभीर मानी जाएगी।यह भी सच है कि चुनावी हार के बाद आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति कोई नई बात नहीं है। लंबे समय से यह प्रवृत्ति देखी जाती रही है कि जब परिणाम उम्मीद के अनुरूप नहीं आते, तो चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठने लगते हैं। लेकिन लोकतंत्र में केवल आरोप पर्याप्त नहीं होते। यदि किसी को चुनावी अनियमितताओं पर संदेह है, तो उसके समर्थन में प्रमाण और तथ्य भी सामने आने चाहिए। बिना ठोस आधार के लगाए गए आरोप केवल राजनीतिक वातावरण को और अधिक अविश्वास से भरते हैं। दूसरी ओर, चुनाव कराने वाली संस्थाओं की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। केवल निष्पक्ष होना पर्याप्त नहीं, बल्कि जनता के सामने निष्पक्ष दिखाई देना भी उतना ही आवश्यक है। मतदाता सूची, मतदान प्रक्रिया, मतगणना और परिणामों की घोषणा तक हर स्तर पर अधिक पारदर्शिता समय की मांग है। यदि कहीं भी शंका की गुंजाइश रह जाती है, तो उसे दूर करने के लिए संस्थाओं को तत्परता से सामने आना चाहिए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी जनता का विश्वास है। यह विश्वास टूटने लगे तो चुनाव केवल औपचारिकता बनकर रह जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को सुरक्षित रखा जाए। लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब आम नागरिक को यह भरोसा होगा कि उसका मत किसी भी परिस्थिति में उसकी आवाज़ बनकर सामने आएगा। यही भरोसा लोकतंत्र की असली नींव है और इसकी रक्षा करना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।

INDIA गठबंधन में दरार के संकेत

डीएमके ने 8 जून की बैठक से बनाई दूरी

लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी INDIA गठबंधन अपने संगठनात्मक ढांचे और भविष्य की रणनीति को मजबूत करने के प्रयास में जुटा है। इसी बीच गठबंधन के प्रमुख सहयोगी दल डीएमके और कांग्रेस के बीच बढ़े राजनीतिक मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। 8 जून को प्रस्तावित विपक्षी बैठक से डीएमके की दूरी ने गठबंधन की एकता और भविष्य को लेकर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

विपक्षी दलों के INDIA गठबंधन के भीतर उभरते मतभेद अब सार्वजनिक रूप से सामने आने लगे हैं। 8 जून को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक से तमिलनाडु की प्रमुख राजनीतिक पार्टी डीएमके (द्रविड़ मुनेत्र कषगम) के अलग रहने के फैसले ने विपक्षी राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। इस घटनाक्रम को विपक्षी एकता के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है और इससे गठबंधन की भविष्य की रणनीति तथा स्थिरता पर सवाल उठने लगे हैं।डीएमके ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि वह इस बैठक में भाग नहीं लेगी। हालांकि पार्टी ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय हित और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े मुद्दों पर वह अन्य विपक्षी दलों के साथ सहयोग जारी रखेगी। लेकिन कांग्रेस के प्रति उसका रुख पहले की तुलना में काफी कठोर दिखाई दे रहा है। डीएमके ने कांग्रेस पर राजनीतिक "विश्वासघात" का आरोप लगाया है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस द्वारा विजय के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन दिए जाने से दोनों दलों के संबंधों में गंभीर तनाव उत्पन्न हुआ है।यह राजनीतिक खींचतान केवल बयानों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि संसद के भीतर भी इसका प्रभाव दिखाई देने लगा है। लोकसभा सचिवालय ने डीएमके सांसदों को कांग्रेस सांसदों से अलग बैठने की अनुमति दे दी है। डीएमके का तर्क है कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में कांग्रेस के साथ बैठना उपयुक्त नहीं है। यह कदम दोनों दलों के बीच बढ़ती दूरी का प्रत्यक्ष संकेत माना जा रहा है और इससे गठबंधन के भीतर विश्वास के संकट की भी झलक मिलती है।8 जून की बैठक में लगभग 15 विपक्षी दलों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। बैठक का मुख्य उद्देश्य हालिया चुनावी परिणामों की समीक्षा करना, विपक्ष की आगामी रणनीति तय करना और संसद के अगले सत्र के लिए साझा एजेंडा तैयार करना है। लेकिन डीएमके की अनुपस्थिति ने बैठक के राजनीतिक महत्व को और बढ़ा दिया है। अब यह केवल रणनीति निर्धारण की बैठक नहीं रह गई है, बल्कि विपक्षी एकता की परीक्षा के रूप में भी देखी जा रही है।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि INDIA गठबंधन के प्रमुख घटकों के बीच मतभेद इसी प्रकार बढ़ते रहे तो इसका सीधा लाभ सत्तारूढ़ भाजपा को मिल सकता है। भारतीय राजनीति में गठबंधन की सफलता काफी हद तक सहयोगी दलों के बीच आपसी विश्वास और समन्वय पर निर्भर करती है। यदि यह विश्वास कमजोर पड़ता है तो विपक्ष की सामूहिक शक्ति भी प्रभावित हो सकती है। फिलहाल कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल गठबंधन को एकजुट बनाए रखने के प्रयास कर रहे हैं। हालांकि डीएमके के इस कदम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विपक्षी मोर्चे के भीतर कई ऐसे मुद्दे मौजूद हैं जिनका समाधान अभी बाकी है। अब देश की राजनीतिक नजरें 8 जून की बैठक पर टिकी हैं। यह बैठक तय कर सकती है कि INDIA गठबंधन भविष्य में और अधिक मजबूत होकर उभरेगा या फिर आंतरिक मतभेद उसकी एकता को कमजोर कर देंगे। विपक्षी राजनीति की दिशा और आगामी चुनावी समीकरणों पर भी इस बैठक के परिणामों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव को लेकर बढ़ा सियासी घमासान

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनावों को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। चुनावी प्रक्रिया के दौरान विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक दबाव बनाने और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं।विपक्ष का दावा है कि कुछ क्षेत्रों में उम्मीदवारों पर नामांकन वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया, जिसके कारण कई सीटों पर मुकाबला कमजोर पड़ गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सर्वोपरि होने चाहिए, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां कई सवाल खड़े कर रही हैं।दूसरी ओर भाजपा ने सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि विपक्ष अपनी राजनीतिक कमजोरी छिपाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहा है। भाजपा का दावा है कि उसके उम्मीदवारों को जनता और जनप्रतिनिधियों का व्यापक समर्थन प्राप्त है, जिसके कारण कई सीटों पर उन्हें स्वाभाविक बढ़त मिली है।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से लगातार अस्थिरता बनी हुई है। दल-बदल, गठबंधन परिवर्तन और नेतृत्व संघर्ष ने राज्य की राजनीतिक तस्वीर को जटिल बना दिया है। ऐसे माहौल में विधान परिषद चुनाव केवल एक सामान्य चुनाव नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का मंच बन गए हैं।विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से पूरे मामले की शिकायत करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और सभी आरोप राजनीतिक लाभ हासिल करने के उद्देश्य से लगाए जा रहे हैं।राज्य के राजनीतिक गलियारों में इस चुनाव को आगामी विधानसभा राजनीति का संकेतक माना जा रहा है। चुनाव परिणाम न केवल दलों की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करेंगे बल्कि भविष्य के गठबंधनों और राजनीतिक रणनीतियों पर भी असर डाल सकते हैं। ऐसे में पूरे राज्य की नजरें अब चुनावी नतीजों और उनके राजनीतिक प्रभाव पर टिकी हुई हैं।

पश्चिम बंगाल में टीएमसी का संकट गहराया बागी विधायकों को मिला स्पीकर का समर्थन

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के भीतर चल रहा आंतरिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद पार्टी को अब अपने ही विधायकों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बागी विधायकों के पक्ष में लिए गए फैसले ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी नेतृत्व की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।विधानसभा अध्यक्ष ने टीएमसी नेतृत्व द्वारा कुछ विधायकों के निष्कासन संबंधी कार्रवाई को स्वीकार नहीं किया। इसके साथ ही बागी गुट के नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता मिलने से राजनीतिक समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं। इस फैसले के बाद विधानसभा में बागी विधायकों की स्थिति और मजबूत हुई है।टीएमसी नेतृत्व ने इस निर्णय पर कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी का कहना है कि बागी विधायक जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। वहीं बागी गुट का आरोप है कि पार्टी नेतृत्व ने लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी की और उनकी बात सुनने की बजाय दमनात्मक रवैया अपनाया।राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद टीएमसी के सामने संगठन को एकजुट बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। कई वरिष्ठ नेता और विधायक भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं को देखते हुए नए विकल्प तलाश रहे हैं। इससे पार्टी के भीतर असंतोष और बढ़ने की आशंका है।टीएमसी सांसदों और नेताओं ने बागी विधायकों पर तीखे हमले किए हैं तथा उन्हें राजनीतिक अवसरवादी बताया है। दूसरी ओर विपक्षी दल इस घटनाक्रम को टीएमसी की कमजोर होती पकड़ का प्रमाण बता रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह विवाद अदालत तक पहुंच सकता है।पश्चिम बंगाल की राजनीति में तेजी से बदलते हालातों के बीच यह मामला राज्य की सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि इसका असर भविष्य की राजनीतिक दिशा और दलों के संगठनात्मक ढांचे पर भी पड़ सकता है।

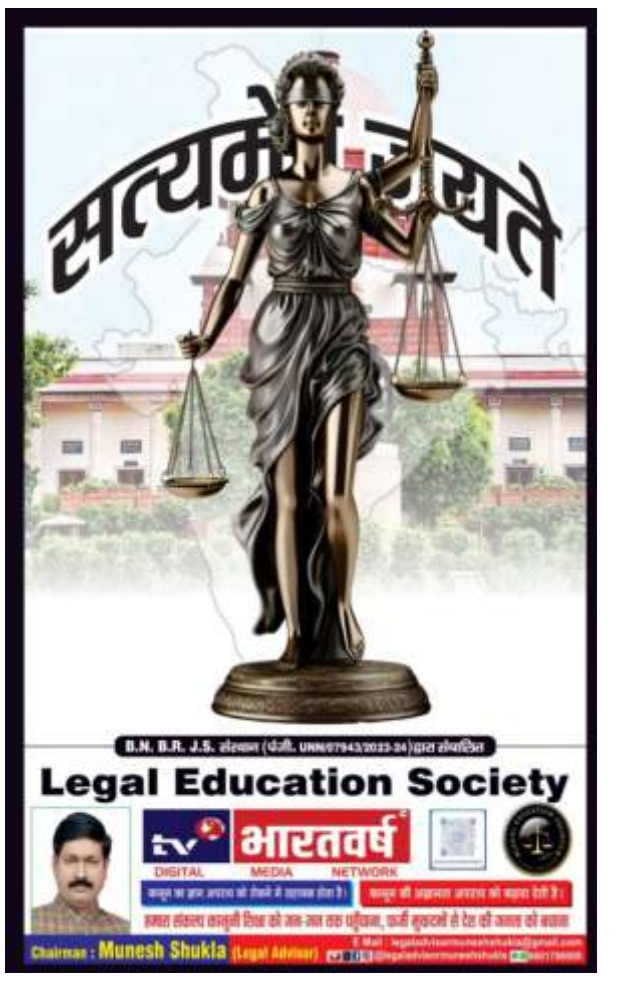

निवेशकों का बढ़ा भरोसा

RBI के फैसले से शेयर बाजार में लौटी मजबूती

भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को सकारात्मक माहौल देखने को मिला। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति द्वारा ब्याज दरों को लेकर लिए गए निर्णय के बाद निवेशकों का विश्वास मजबूत हुआ और बाजार में व्यापक खरीदारी दर्ज की गई। कारोबार के दौरान प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ कारोबार करते दिखाई दिए। बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट क्षेत्र के शेयरों में विशेष रूप से तेजी देखने को मिली।बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि RBI द्वारा ब्याज दरों में स्थिरता बनाए रखने अथवा निवेशकों की अपेक्षाओं के अनुरूप निर्णय लेने से बाजार को सकारात्मक संकेत मिला है। पिछले कुछ महीनों से वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, महंगाई के दबाव और भू-राजनीतिक तनावों के कारण निवेशकों के बीच सतर्कता का माहौल बना हुआ था। ऐसे समय में केंद्रीय बैंक के संतुलित रुख ने बाजार को स्थिरता का संदेश दिया है।विशेषज्ञों के अनुसार ब्याज दरों में अचानक वृद्धि न होने से उद्योगों और कारोबारों को राहत मिलेगी। इससे कंपनियों की उधारी लागत नियंत्रित रहेगी और निवेश गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। बैंकिंग क्षेत्र के लिए भी यह स्थिति अनुकूल मानी जा रही है क्योंकि ऋण मांग में वृद्धि होने की संभावना बनी रहती है। यही कारण रहा कि प्रमुख निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली।शेयर बाजार के जानकारों का कहना है कि RBI के फैसले से घरेलू निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। बीते कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है। मजबूत जीडीपी वृद्धि, सरकारी पूंजीगत व्यय और बढ़ते उपभोक्ता खर्च ने निवेशकों को भारतीय बाजार के प्रति आशावादी बनाए रखा है। केंद्रीय बैंक की नीतिगत स्थिरता ने इस विश्वास को और मजबूत किया है।हालांकि बाजार के लिए कुछ चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव चिंता का विषय है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए तेल की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर महंगाई और व्यापार घाटे पर पड़ सकता है। इसके अलावा पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक अर्थव्यवस्था में धीमी वृद्धि की आशंकाएं भी निवेशकों को सतर्क बनाए हुए हैं।विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की गतिविधियां भी आने वाले समय में बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। यदि विदेशी निवेश का प्रवाह मजबूत बना रहता है तो भारतीय शेयर बाजार को अतिरिक्त समर्थन मिल सकता है। वहीं मानसून की स्थिति पर भी निवेशकों की नजर बनी हुई है, क्योंकि कृषि उत्पादन और ग्रामीण मांग का भारतीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।बाजार विश्लेषकों का मानना है कि यदि महंगाई नियंत्रित रहती है, मानसून सामान्य रहता है और वैश्विक परिस्थितियां अधिक प्रतिकूल नहीं होतीं, तो भारतीय शेयर बाजार आने वाले महीनों में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकता है। फिलहाल RBI के ताजा फैसले ने निवेशकों को राहत प्रदान की है और बाजार में सकारात्मक धारणा को मजबूत किया है। यही कारण है कि सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन निवेशकों के चेहरे पर उत्साह और विश्वास दोनों दिखाई दिए।

RBI ने ब्याज दरें यथावत रखीं, विकास दर अनुमान घटाया

भारतीय रिजर्व बैंक (R B I) ने अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर यथावत रखने का फैसला किया है। केंद्रीय बैंक का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है। बढ़ती ऊर्जा कीमतें, अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता के बीच RBI ने सतर्क रुख अपनाया है।मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद RBI ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक विकास दर (GDP Growth) का अनुमान घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है। इससे पहले विकास दर का अनुमान अधिक रखा गया था। वहीं, महंगाई दर के अनुमान को बढ़ाकर 5.1 प्रतिशत कर दिया गया है, जो यह संकेत देता है कि आने वाले महीनों में कीमतों पर दबाव बना रह सकता है।RBI के अनुसार, वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक विकास को समर्थन देने के साथ-साथ महंगाई को नियंत्रित रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। केंद्रीय बैंक का मानना है कि ब्याज दरों में फिलहाल कोई बदलाव न करना अर्थव्यवस्था के लिए संतुलित कदम होगा। इससे उद्योगों, कारोबारों और बैंकिंग क्षेत्र को स्थिरता मिलेगी तथा ऋण लेने वालों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।इसके अलावा RBI ने रुपये को मजबूत बनाए रखने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कुछ अतिरिक्त उपायों की भी घोषणा की है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्थिर ब्याज दरों से निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। हालांकि बढ़ती महंगाई और वैश्विक परिस्थितियां आगे भी नीति निर्माताओं के लिए चुनौती बनी रह सकती हैं। शेयर बाजार ने RBI के इस फैसले का सकारात्मक स्वागत किया। निवेशकों को उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक की संतुलित नीति आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के साथ वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में भी मददगार साबित होगी।

लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन गिरे 16 विकेट

फीफा विश्व कप 2026 आगाज से पहले टीमों ने तेज की तैयारियां

फीफा विश्व कप 2026 के उद्घाटन में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और दुनिया भर की प्रमुख फुटबॉल टीमें अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई हैं। इस बार विश्व कप का आयोजन अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त मेजबानी में हो रहा है। पहली बार 48 टीमें टूर्नामेंट में भाग लेंगी, जिससे प्रतियोगिता पहले की तुलना में अधिक व्यापक और रोमांचक होने की उम्मीद है।टूर्नामेंट से पहले विभिन्न देशों की टीमों ने अभ्यास मैचों और प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया है। खिलाड़ी फिटनेस, रणनीति और टीम संयोजन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। फुटबॉल विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पारंपरिक ताकतों के अलावा एशियाई और अफ्रीकी टीमें भी बड़ा उलटफेर कर सकती हैं।आयोजकों के अनुसार विश्व कप के लिए सभी स्टेडियम लगभग तैयार हैं। टिकटों की बिक्री में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लाखों दर्शकों के तीनों देशों में पहुंचने की संभावना है। विश्व कप केवल खेल आयोजन नहीं बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।फुटबॉल प्रेमियों की नजरें अब उद्घाटन मुकाबले और उन स्टार खिलाड़ियों पर टिकी हैं जो अपने देशों को खिताब दिलाने का सपना लेकर मैदान में उतरेंगे। विश्व कप के शुरू होने के साथ ही दुनिया भर में फुटबॉल का उत्साह चरम पर पहुंचने की उम्मीद है।

महिला टी-20 विश्व कप की तैयारियां शुरू क्वालीफिकेशन व्यवस्था पर बहस

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा महिला टी-20 विश्व कप 2026 की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। हालांकि टूर्नामेंट की क्वालीफिकेशन प्रणाली को लेकर क्रिकेट जगत में बहस शुरू हो गई है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अधिक टीमों को सीधे प्रवेश दिए जाने से प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है।इस बार 12 टीमों के टूर्नामेंट में 10 टीमों को स्वतः क्वालीफिकेशन दिया गया है, जबकि केवल दो स्थान क्वालीफायर के माध्यम से तय होंगे। क्रिकेट विश्लेषकों का कहना है कि इससे उभरती टीमों के लिए अवसर सीमित हो सकते हैं। दूसरी ओर आईसीसी का तर्क है कि महिला क्रिकेट के विस्तार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए यह व्यवस्था आवश्यक है।भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीमें खिताब की प्रमुख दावेदार मानी जा रही हैं। भारतीय महिला टीम ने हाल के वर्षों में शानदार प्रदर्शन किया है और प्रशंसकों को उससे बड़ी उम्मीदें हैं।क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि विश्व कप महिला क्रिकेट को और लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आने वाले महीनों में टीमों की तैयारियां और चयन प्रक्रिया चर्चा का प्रमुख विषय बनी रहेंगी।

रजत पाटीदार को इंडिया ए में जगह मिलने की संभावना

रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने बैक टू बैक दो बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी से अपनी टीम को कई मैचों में जीत दिलाने काम काम किया, लेकिन उनकी टीम इंडिया में एंट्री को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि अब चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं। रजत पाटीदार को भारत की नेशनल टीम में तो नहीं, लेकिन इंडिया ए में जगह मिलने की संभावना जताई जा रही है। वे ऋतुराज गायकवाड की जगह ले सकते हैं, जो विराट कोहली को चोटिल होने के बाद नेशनल टीम में रिप्लेस कर सकते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है। इसका आगाज 13 जून से होना है। बीसीसीआई ने इसके लिए पहले ही टीम इंडिया का ऐलान कर दिया था। इस बीच चार जून को दोपहर में अचानक खबर सामने आई कि विराट कोहली हैमस्ट्रिंग चोट के कारण पूरी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर बीसीसीआई की ओर से पुष्टि नहीं की गई है। अब पता चला है कि ऋतुराज गायकवाड को भारतीय टीम में कोहली के रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया जा सकता है। लेकिन गायकवाड इससे पहले ए टीम में शामिल किए गए थे, जो श्रीलंका में तीन देशों की वनडे सीरीज में खेलने जा रही है। इस बीच पत ये भी चला है कि ऋतुराज गायकवाड अगर टीम इंडिया में कोहली के रिप्लेसमेंट के तौर पर आते हैं तो गायकवाड की जगह रजत पाटीदार की एंट्री ए टीम में हो सकी है। ये खबर इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले सी दी है। 9 जून से श्रीलंका में तीन देशों की सीरीज खेली जानी है। इसमें भारत और श्रीलंका के अलावा तीसरी टीम अफगानिस्तान है। सभी ए टीमें यहां खेलेंगी। भारतीय ए टीम की कमान तिलक वर्मा के पास है और वैभव सूर्यवंशी को भी इसमें जगह दी गई है। मजे की बात ये है कि पहले जब त्रिकोणीय सीरीज के लिए भारत की ए टीम का ऐलान किया गया था, तब ऋतुराज गायकवाड को उस टीम में भी जगह नहीं मिली थी, लेकिन अचानक रियान पराग घायल हो गए तो आनन फानन में गायकवाड का नाम जोड़ दिया गया, लेकिन अब वे फिर से टीम इंडिया में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं।

कंगना की फिल्म का पहला गाना रिलीज

नयी दिल्ली। अभिनेत्री कंगना रनौत अपनी आगामी फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' के जरिए बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं। फिल्म की रिलीज से पहले निर्माताओं ने इसका पहला गीत 'नब्ज नब्ज' जारी कर दिया है, जिसे दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसने अपनी भावनात्मक कहानी और दमदार विषयवस्तु के कारण लोगों का ध्यान खींचा था। अब इस नए गीत ने फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ा दी है।

कंपनी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुए 'नब्ज नब्ज' को मशहूर गायिका श्रेया घोषाल ने अपनी मधुर आवाज दी है। गीत के बोल फिल्म के निर्देशक मनोज तापड़िया ने लिखे हैं, जबकि इसका

संगीत अमन पंत ने तैयार किया है। गाने में कंगना रनौत नर्स गीता माधव के किरदार में नजर आ रही हैं, जो अस्पताल में मरीजों की सेवा और देखभाल करती दिखाई देती हैं। गीत फिल्म की संवेदनशील कहानी और मानवीय भावनाओं को प्रभावी ढंग से सामने लाता है। भारत भाग्य विधाता मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के दौरान कामा अस्पताल में घटी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित फिल्म है। फिल्म में कंगना रनौत के अलावा गिरिजा ओक, स्मिता तांबे और आदित्य मिश्रा भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। मनोज तापड़िया के निर्देशन में बनी यह फिल्म साहस, कर्तव्य और मानवता की कहानी को बड़े पर्दे पर पेश करेगी। फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।

तीसरी शादी को लेकर आमिर खान ने तोड़ी चुप्पी

नयी दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ शादी की खबरों पर आधिकारिक मुहर लगा दी है। लंबे समय से दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चाएं चल रही थीं, लेकिन अब अभिनेता ने स्वयं पुष्टि की है कि वह 5 जुलाई को गौरी के साथ विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। यह घोषणा उस बयान के कुछ समय बाद आई है, जिसमें आमिर ने कहा था कि फिलहाल शादी उनकी प्राथमिकता नहीं है। बताया जा रहा है कि आमिर और गौरी पिछले एक वर्ष से अधिक समय से एक-दूसरे के साथ रह रहे हैं। एक बातचीत के दौरान आमिर खान ने कहा कि शादी की खबर पूरी तरह सच है और दोनों ने अपने रिश्ते को अगले पड़ाव तक ले जाने का फैसला किया है। अभिनेता के अनुसार वह और गौरी अपने रिश्ते को लेकर बेहद गंभीर हैं और उन्हें लगता है कि अब शादी उनके संबंध की स्वाभाविक प्रगति है।

दिल्ली मेट्रो की लड़ाई वायरल, भड़के सोशल मीडिया यूजर्स

बहस के बाद लड़की ने जड़ा बुजुर्ग को थप्पड़

आए दिन दिल्ली मेट्रों में लड़ाई-झगड़े या बहस के वीडियो सामने आते रहते हैं. एक ऐसा ही वीडियो चर्चमा में है, जिसमें एक लड़की सीट को लेकर एक शख्स को थप्पड़ लगाती दिख रही है.

दिल्ली मेट्रो में लड़ाई-झगड़े से जुड़े वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं. आए दिन कोई बहस, डांस या झगड़े का वीडियो सामने आते रहते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ने मेट्रो में सफर कर रहे एक शख्स को थप्पड़ लगा दिया.

सोशल मीडिया पर दिल्ली मेट्रो का एक वीडियो घूम रहा है. इसमें सीट को लेकर एक महिला और एक पुरुष के बीच तीखी बहस होती दिखाई दे रही है. देखते ही देखते यह बहस हाथापाई में तब्दील हो गई. जब महिला ने शख्स को थप्पड़ जड़ दिया. इस घटना का किसी यात्री ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. उसके बाद से यह वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @ghar-kekalesh नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इसका कैप्शन है - दिल्ली मेट्रो के अंदर सीट को लेकर लड़की और अंकल के बीच कलेश. इस वीडियो में मेट्रो में सीट को लेकर एक लड़की और सीट पर बैठे शख्स के बीच तीखी बहस होती दिखाई देती है. फिर अचानक से लड़की उस आदमी को थप्पड़ लगा देती है.

इसके बाद वो शख्स भी खड़ा हो जाता है और लड़की को मारने के लिए हाथ उठाता है, फिर हाथ रोक लेता है. दोनों के बीच में एक महिला बीच-बचाव करती दिखाई देती है. लड़की लगातार ऊंची आवाज में सामने बैठे शख्स से बहस करती रह जाती है. इसके बाद उस शख्स को आसपास के लोग समझाकर बैठा देते हैं और लड़की आगे बढ़ जाती है. ⊙

टकराव हाथापाई में तब्दील

जैसे-जैसे लड़की का गुस्सा बढ़ता गया, टकराव हाथापाई में तब्दील हो गई. एक समय ऐसा भी आया जब महिला ने बहस के दौरान पुरुष को थप्पड़ मार दिया. पुरुष तुरंत अपनी सीट से उठा और उसकी ओर बढ़ा, जिससे स्थिति और भी बिगड़ गई. इस वीडियो पर काफी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक शख्स ने लिखा है - दिल्ली मेट्रो को ऐसे झगड़ों के लिए सख्त नियम बनाने चाहिए. ⊙

स्नेक शो में सपेरे के हाथ से भागा सांप, टूरिस्ट को डसा

इजिप्ट में के एक रिसोर्ट में हाल ही में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई. इजिप्ट के पिरामिड देखने और वहां घूमने आए एक जर्मन टूरिस्ट की विचित्र तरीके से मौत हो गई. वह शख्स रिसोर्ट में सांप के करतब (स्नेक शो) देख रहा था. यह स्नेक शो उसके टूर पैकेज के एक एक्सक्लूसिव ऑफर का हिस्सा था. करतब के दौरान जब सपेरा सांप को टूरिस्ट के नजदीक ले गया तो वह फिसकर उसके पैंट में घुस गया और उसे काट लिया. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि एक जर्मन पर्यटक की तब मौत हो गई. ⊙

रणवीर सिंह को मिली राहत, 'डॉन 3' विवाद में FWICE ने वापस लिया फैसला

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को बड़ी राहत मिली है। फिल्म उद्योग से जुड़े प्रमुख संगठन FWICE (फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज) ने उनके खिलाफ चल रहे असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया है। यह निर्णय फिल्म उद्योग के विभिन्न संगठनों, निर्माताओं और संबंधित पक्षों के बीच हुई बातचीत तथा आपसी सहमति के बाद लिया गया है।पिछले कुछ समय से रणवीर सिंह और FWICE के बीच विवाद चर्चा का विषय बना हुआ था। संगठन ने कुछ मुद्दों को लेकर अभिनेता के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था, जिसके कारण उनके आगामी फिल्मी प्रोजेक्ट्स पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही थी। विशेष रूप से उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म डॉन 3 इस विवाद के कारण लगातार सुर्खियों में बनी हुई थी। फिल्म से जुड़े प्रशंसकों और उद्योग जगत की निगाहें इस मामले के समाधान पर टिकी हुई थीं।हालांकि हाल के दिनों में दोनों पक्षों के बीच संवाद का दौर शुरू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लिया गया। FWICE ने यह स्पष्ट किया कि बातचीत के माध्यम से कई मुद्दों पर सहमति बनी है और उद्योग के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया गया है। इस कदम को फिल्म उद्योग में सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है।फिल्म कारोबार से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ 'डॉन 3' को मिलेगा। लंबे समय से चर्चा में बनी यह फिल्म दर्शकों के बीच भारी उत्सुकता का विषय है। रणवीर सिंह पहली बार प्रतिष्ठित 'डॉन' फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, इसलिए फिल्म को लेकर पहले से ही काफी अपेक्षाएं हैं। अब विवाद समाप्त होने के बाद फिल्म के निर्माण, प्रचार और अन्य गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है।रणवीर सिंह वर्तमान समय में हिंदी फिल्म उद्योग के सबसे लोकप्रिय और व्यस्त अभिनेताओं में शामिल हैं। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में कई सफल फिल्मों के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाई है। उनके प्रशंसक 'डॉन 3' सहित उनकी आगामी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।विश्लेषकों का कहना है कि यह घटनाक्रम फिल्म उद्योग में संवाद, सहयोग और आपसी समझ की महत्ता को रेखांकित करता है। किसी भी विवाद का समाधान बातचीत के माध्यम से निकालना उद्योग के लिए लाभकारी होता है। FWICE और रणवीर सिंह के बीच विवाद का समाप्त होना न केवल संबंधित पक्षों के लिए राहत की खबर है, बल्कि इससे फिल्म उद्योग में सकारात्मक और सहयोगात्मक माहौल को भी बढ़ावा मिलेगा। अब उम्मीद की जा रही है कि 'डॉन 3' से जुड़ी सभी गतिविधियां बिना किसी बाधा के आगे बढ़ेंगी और दर्शकों को जल्द ही इस बहुप्रतीक्षित फिल्म की नई झलक देखने को मिलेगी।

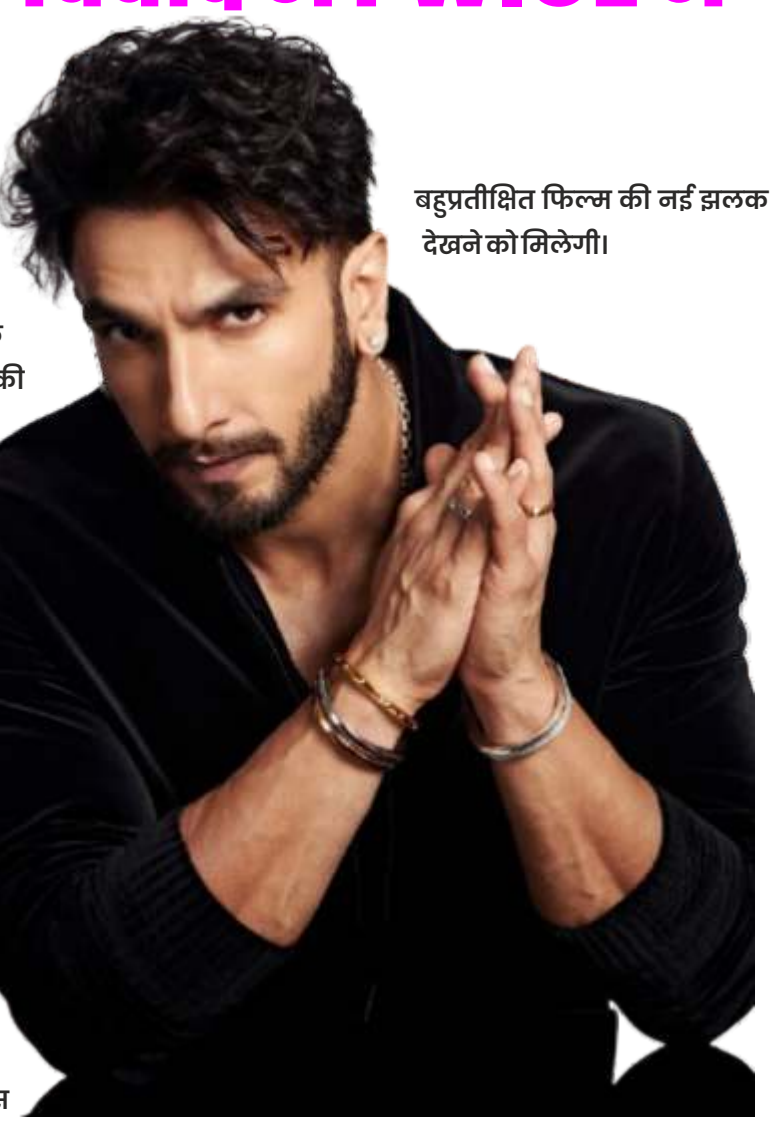

राजा कंसा किला विवाद पर गरमाई सियासत:

लाखन आर्मी की 'पासी स्वाभिमान यात्रा' से चुनावी हलकों में हलचल

लाखन आर्मी अपने दावे के समर्थन में अंग्रेजी गजेटियर और स्थानीय ऐतिहासिक विवरणों का हवाला दे रही है। संगठन का कहना है कि उपलब्ध ऐतिहासिक अभिलेखों में काकोरी और आसपास के क्षेत्र में 11वीं सदी के दौरान राजा कंसा पासी के शासन का उल्लेख मिलता है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी लखनऊ का एक पुराना ऐतिहासिक और धार्मिक विवाद एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। मलिहाबाद क्षेत्र के कसमंडी कलां स्थित कथित राजा कंसा किले और उसके भीतर मौजूद बताए जा रहे शिव मंदिर को लेकर लाखन आर्मी ने बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी ने प्रदेशव्यापी "पासी स्वाभिमान यात्रा" निकालने की घोषणा करते हुए कहा है कि शिव मंदिर की मुक्ति और पासी समाज की ऐतिहासिक विरासत की रक्षा के लिए व्यापक जनसमर्थन जुटाया जाएगा। सूरज पासी ने बताया कि यह यात्रा 9 जून को हरदोई से शुरू होगी और एक महीने तक प्रदेश के विभिन्न जिलों से गुजरते हुए 9 जुलाई को लखनऊ पहुंचकर समाप्त होगी। यात्रा के समापन पर राजधानी में एक विशाल "पासी स्वाभिमान महासम्मेलन" आयोजित किया जाएगा। संगठन का दावा है कि यह अभियान केवल एक धार्मिक स्थल की मुक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि पासी समाज के इतिहास, स्वाभिमान और सांस्कृतिक पहचान को पुनर्स्थापित करने का प्रयास भी है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच यह विवाद राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सामाजिक और ऐतिहासिक पहचान से जुड़े मुद्दे चुनावी माहौल में तेजी से प्रभाव डालते हैं। ऐसे समय में राजा कंसा किला और शिव मंदिर का मामला सामने आने से राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। लाखन आर्मी का कहना है कि वह इस मुद्दे को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि ऐतिहासिक विरासत और सामाजिक सम्मान के प्रश्न के रूप में उठा रही है। संगठन का दावा है कि वर्षों से उपेक्षित इस स्थल को उचित पहचान और संरक्षण मिलना चाहिए। विवाद का केंद्र मलिहाबाद क्षेत्र के कसमंडी कलां में स्थित एक स्थल है, जिसे मुस्लिम समुदाय मजार और मस्जिद से जुड़ा धार्मिक परिसर मानता है, जबकि लाखन आर्मी और पासी समाज के कुछ लोग इसे राजा कंसा का ऐतिहासिक किला बताते हैं। सूरज पासी का आरोप है कि किले के भीतर स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया और समय के साथ वहां मजार तथा मस्जिद का स्वरूप विकसित हो गया। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष इन दावों को खारिज करता रहा है और स्थल को अपने धार्मिक महत्व का हिस्सा बताता है। इसी दावे और प्रतिदावे के कारण पिछले कुछ महीनों से दोनों पक्षों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रशासन को भी कई बार स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा है। विवाद उस समय और अधिक बढ़ गया जब बकरीद से पहले लाखन आर्मी ने कसमंडी कलां स्थित स्थल पर हनुमान चालीसा पाठ करने की घोषणा कर दी। संगठन का कहना था कि यह स्थान मूल रूप से हिंदू धार्मिक स्थल है और वहां पूजा-अर्चना की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि, संभावित तनाव को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने दोनों पक्षों की गतिविधियों पर रोक लगा दी। न तो लाखन आर्मी को वहां हनुमान चालीसा पाठ की अनुमति मिली और न ही मुस्लिम समुदाय को नमाज अदा करने की इजाजत दी गई।

विक्षोभ के चलते पूरे प्रदेश में मौसम बदलने की संभावना

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

उत्तर प्रदेश में बृहस्पतिवार को एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ। इसके असर से पूर्वी और पश्चिमी संभागों के कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ कहीं मध्यम तो कही हल्की बारिश हुई। गोरखपुर में सर्वाधिक 21.7 मिमी बारिश दर्ज हुई। वहीं बाराबंकी, सीतापुर, प्रयागराज, मेरठ, अलीगढ आदि में हल्की बूंदाबांदी हुई। इस कमजोर विक्षोभ के असर से प्रदेश भर में तापमान में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई। शुक्रवार के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के 21 जिलों में आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 42 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बूंदे पड़ने की संभावना जताई गई है। बांदा 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म जिला दर्ज किया गया। इसके अलावा वाराणसी में 42 डिग्री, झांसी में 41.9 डिग्री और बहराइच में 40.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार नए विक्षोभ के असर से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भी आंधी और छिटपुट बूंदाबांदी के आसार हैं। हालांकि तापमान में बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल नहीं है। बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर व आस पास के इलाके।

मायावती ने हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर इकाइयों की समीक्षा बैठक की चुनावी तैयारी पर जोर

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर इकाइयों की समीक्षा बैठक की। बैठक में संगठन की जमीनी मजबूती, जनाधार विस्तार और आगामी चुनावी तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गईमायावती ने पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने के साथ चुनावी सफलता को भी प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज को बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए एकजुट होकर बीएसपी को मजबूत बनाना होगा। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोगों को अपने वोट की सुरक्षा को आत्मसम्मान, इज्जत और अधिकारों की सुरक्षा के समान महत्व देने के लिए जागरूक करने का आह्वान किया। बैठक में हिमाचल प्रदेश के हालिया स्थानीय निकाय चुनावों के बाद बने राजनीतिक हालात की भी समीक्षा की गई। इस दौरान पार्टी नेताओं ने कहा कि राज्य में कांग्रेस और भाजपा के प्रति लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है, ऐसे में बीएसपी के लिए एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरने का अवसर है। जम्मू-कश्मीर इकाई की समीक्षा के दौरान पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। पार्टी नेताओं ने बताया कि लंबे समय से लंबित यह मांग अब लोगों के लिए चिंता और निराशा का कारण बनती जा रही है। उनका मानना है कि राज्य का दर्जा न मिलने से क्षेत्र के विकास, प्रशासनिक व्यवस्था और जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मायावती ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर सहित देश के कई राज्यों में बहुजन समाज आज भी गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और पिछड़ेपन जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आंबेडकरवादी विचारधारा के आधार पर समाज को संगठित कर राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में सक्रियता बढ़ाने का आह्वान किया।

राजनाथ सिंह ने अपर्णा यादव से की मुलाकात

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह शुक्रवार को तीन दिवसीय दौरे पर राजधानी पहुंचे। सुबह 11:30 बजे चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद उनका स्वागत उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और महापौर सुषमा खर्कवाल ने किया। रक्षामंत्री ने सबसे पहले हिंद नगर में व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष रहे दिवंगत अशोक मोतियानी के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। इसके बाद उन्होंने दिवंगत कपड़ा व्यापारी दर्शन लाल कुर्ती के आवास पहुंचकर परिजनों को ढाढ़स बंधाया और अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं। दोपहर 12:15 बजे राजनाथ सिंह ने कैंट स्थित कस्तूरबा पार्क में "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत पौधरोपण किया। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। पौधरोपण कार्यक्रम के बाद रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के कैंट स्थित आवास पहुंचे। यहां उन्होंने हाल ही में दिवंगत हुए प्रतीक यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाजपा नेत्री अपर्णा बिष्ट यादव के पति स्वर्गीय प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि दी।

22 साल की युवती ने ओवरब्रिज से कूदकर जान दे दी

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ के मड़ियांव थाना क्षेत्र में एक 22 साल की युवती ने ओवरब्रिज से कूदकर जान दे दी। उसने घरवालों से जिद करके प्रेमी से अपनी शादी तय कराई थी। घरवालों के अनुसार, वह ज्यादातर अपने प्रेमी और उसके परिवार के साथ ही समय बिताती थी। गुरुवार रात प्रेमी से ही बात करते हुए घर के बाहर निकली और ओवरब्रिज से कूद गई। मड़ियांव के कसाईबाड़ा निवासी मजदूर रामकिशन गौतम की बेटी शिल्पी गौतम (22) ने यह कदम उठाया। पुलिस के मुताबिक, घटना से पहले वह अपने प्रेमी से फोन पर बात कर रही थी। परिजनों का आरोप है कि बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। बहन लक्ष्मी ने बताया कि गुरुवार रात करीब 10 बजे पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा था। इसी दौरान शिल्पी मोबाइल लेकर घर से बाहर चली गई। वह अक्सर प्रेमी से बात करने के लिए बाहर निकल जाती थी, इसलिए किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। काफी देर तक वापस न लौटने पर परिवार को लगा कि वह प्रेमी के घर चली गई होगी।परिजनों के अनुसार शिल्पी का पास के ही एक युवक से प्रेम संबंध था। परिवार की सहमति के बाद दोनों की शादी तय हो चुकी थी। नवरात्र में सगाई और अगले साल फरवरी में विवाह की तैयारी थी। लेकिन शिल्पी चाहती थी कि शादी अगले साल नहीं बल्कि इसी साल कर दी जाए।

अस्पताल को 10 व्हीलचेयर भेंट

विश्व पर्यावरण दिवस पर उन्नाव लालगंज हाईवेज की अनूठी पहल

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उन्नाव लालगंज हाईवेज प्राइवेट लिमिटेड (एनएच-31) ने सामाजिक उत्तरदायित्व (C S R) के तहत जनकल्याण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की। यह कार्यक्रम पीआईयू कानपुर एवं आरओ लखनऊ के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया, जिसमें समाज सेवा और पर्यावरण जागरूकता से जुड़े कई कार्यक्रम संपन्न हुए।कार्यक्रम के तहत स्थानीय सिविल अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए कंपनी द्वारा 10 मेडिकल व्हीलचेयर निःशुल्क प्रदान की गईं। इस पहल से अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले मरीजों, बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों को काफी सुविधा मिलेगी। अस्पताल प्रशासन ने कंपनी के इस सहयोग की सराहना करते हुए इसे सामाजिक उत्तरदायित्व का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा को लेकर विशेष शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया गया। मुख्य अतिथियों एवं कंपनी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने

सामूहिक रूप से पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और हरित विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सभी ने अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने तथा पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाए रखने का संकल्प लिया।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीघापुर के माननीय नायब तहसीलदार श्री विजय रंजन श्रीवास्तव, रेसिडेंट इंजीनियर श्री विश्वनाथ तिवारी, बिहार थाना प्रभारी श्री राहुल सिंह तथा बीघापुर थाना प्रभारी श्री अरविंद कुमार उपस्थित रहे। अतिथियों ने कंपनी की इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि निजी संस्थानों की ऐसी सामाजिक भागीदारी से समाज के जरूरतमंद वर्गों को प्रत्यक्ष लाभ मिलता है और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता भी बढ़ती है।कंपनी प्रबंधन ने कहा कि उन्नाव लालगंज हाईवेज प्राइवेट लिमिटेड केवल सड़क अवसंरचना के विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन कर रही है। भविष्य में भी जनहित, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी।विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित यह कार्यक्रम सामाजिक सेवा, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और पर्यावरण संरक्षण के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता का प्रतीक बनकर उभरा।

दिल्ली हादसे के बाद होटल-अस्पतालों की जांच

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

दिल्ली में हुए अग्निकांड के बाद शासन के निर्देश पर अग्निशमन विभाग की टीमों ने होटलों, अस्पतालों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की चेकिंग की। 35 भवनों की जांच में कहीं भी मानक पूरे नहीं मिले। कहीं निकास के रास्तों पर अतिक्रमण मिला तो कहीं फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं या उपयोगी नहीं मिला। सीएफओ ने नोटिस जारी कर तत्काल सुधार करने और 15 दिन बाद दोबारा जांच में सुधार न मिलने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस के निर्देश पर सीएफओ अनूप सिंह, अग्निशमन अधिकारी राममिलन भारती ने ने टीम ने सघन जांच की।

गदनखेड़ा बाईपास स्थित आरवी टॉवर होटल का निरीक्षण किया। संचालन की एनओसी नहीं मिली। फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं लगा मिला। संचालक को नोटिस देकर जल्द सुधार का निर्देश दिया। होटल के बगल में आरा मशीन के आसपास लकड़ियां रखी मिलीं तो उन्हें भी हटवाया गया। अल हबीब होटल में भी टीम को आग से बचाव के इंतजाम नहीं मिले। गदनखेड़ा बाईपास स्थित गोल्डन बार, बड़ा चौराहा स्थित माया-इन के संचालक फायर एनओसी नहीं दिखा सके। यहां अग्नि सुरक्षा के मानक भी पूरे नहीं मिले। सीएफओ ने बताया कि होटलों की जांच के दौरान भवनों में स्थापित फायर एक्सटिंग्विशर (अग्निशमन यंत्र), होजरील, स्प्रिंकलर सिस्टम और टेरिस फायर पंपों की जांच की गई है। व्यवस्थाएं सही नहीं मिली हैं, नोटिस जारी किया है।

पोनी रोड की कुल चौड़ाई आठ मीटर होगी

उन्नाव में लंबे समय से प्रतीक्षित पोनी रोड चौड़ीकरण परियोजना को अब गति मिल गई है। सदर विधायक पंकज गुप्ता ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजना की समीक्षा की। बैठक में निर्णय लिया गया कि शुक्रवार से जमीनी स्तर पर कार्य शुरू किया जाएगा। पोनी रोड का शिलान्यास पहले ही हो चुका था, लेकिन स्थानीय विवाद और विरोध के कारण निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ सका था, जिससे क्षेत्रीय लोगों में असंतोष भी बढ़ रहा था। बैठक में तय किया गया कि पोनी रोड की कुल चौड़ाई आठ मीटर होगी। सड़क के बीच से दोनों ओर चार-चार मीटर तक चौड़ीकरण किया जाएगा। इसके लिए प्रभावित निर्माणों का चिन्हांकन कार्य शुक्रवार से शुरू होगा। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता एच.डी. अहरवार ने बताया कि पहले सर्वे और नापजोख किया जाएगा। जिन मकानों और दुकानों का हिस्सा सड़क की सीमा में आएगा, उनसे स्वयं अतिक्रमण हटाने की अपील की जाएगी। यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी से कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुआवजे के मुद्दे पर भी चर्चा हुई, लेकिन प्रभावित लोगों को मुआवजा मिलेगा या नहीं, इस पर स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आ सकी, जिससे लोगों में असमंजस बना हुआ है। बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता भारत गौतम ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के मद्देनजर बिजली पोल और लाइनों की शिफ्टिंग की जाएगी। इसके लिए जेई और एसडीओ स्तर के अधिकारियों को मौके का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही भूमिगत हाईटेंशन (एचटी) लाइन बिछाने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, लाइन शिफ्टिंग के लिए विधायक निधि से पहले ही 1.60 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 30 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। शेष राशि से पूरा कार्य संभव नहीं होने पर नया इस्टीमेट तैयार कर अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाएगी, जिस पर विधायक ने सकारात्मक आश्वासन दिया है।

सभासद ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव के बांगरमऊ नगर पालिका क्षेत्र में सड़क निर्माण न होने से नाराज एक सभासद ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। वार्ड की सड़क बनाने की मांग को लेकर सभासद हरिओम तिवारी अधिशासी अधिकारी (ईओ) गूंजन सिंह के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने पहले हाथ जोड़कर गुहार लगाई और फिर दंडवत होकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सभासद हरिओम तिवारी का आरोप है कि उनके वार्ड में पिछले करीब चार महीनों से सड़क निर्माण का कार्य लंबित है। इसके कारण स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कई बार शिकायतें और अनुरोध करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। कार्यालय पहुंचकर सभासद ने अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर सड़क निर्माण की मांग की। जब उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला, तो उन्होंने कार्यालय में ही दंडवत होकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि नगर पालिका अध्यक्ष और अधिकारी उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो वे जनता की समस्या लेकर कहां जाएंगे। सभासद ने बताया कि सड़क की खराब स्थिति के कारण वार्ड के लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि बरसात के मौसम से पहले सड़क का निर्माण न होने पर स्थिति और भी बिगड़ सकती है। उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र की जनता की आवाज उठाने के लिए मजबूर होकर यह प्रदर्शन कर रहे हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नगर पालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब जनप्रतिनिधियों को भी अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह का कदम उठाना पड़ रहा है, तो आम जनता की समस्याओं का अंदाजा लगाया जा सकता है।

कीटनाशक खाने से नौ कुत्ते मरे पशु चिकित्सक ने गांव पहुंचकर इलाज का प्रयास किया

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

आसीवन के कनिगांव में कीटनाशक खाने से नौ कुत्तों की हालत बिगड़ने लगी। सूचना पर पशु चिकित्सक पहुंचे लेकिन तब तक आठ कुत्तों की मौत हो चुकी थी। एक कुत्ते की इलाज के दौरान मौत हो गई। कनिगांव में बुधवार रात अज्ञात लोगों ने गांव के कुत्तों को कीटनाशक दवा खिला दी। इससे कुत्तों की हालत बिगड़ने लगी। एक साथ कई कुत्तों की हालत खराब देख ग्रामीण बलराम सिंह ने पीआरवी के साथ प्रधान प्रतिनिधि वेद चौरसिया को भी सूचना दी। प्रधान प्रतिनिधि ने तत्काल पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज सिंह को बुलाया लेकिन तब तक आठ कुत्तों की मौत हो चुकी थी। वहीं एक गंभीर अवस्था में मिले कुत्ते का इलाज किया लेकिन उसकी भी मौत हो गई। कुल नौ कुत्तों की मौतों की सूचना पर पुलिस ने जांच की। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज सिंह बताया कि कीटनाशक अधिक प्रभावशाली था इस वजह से मौत हो गई है। ग्रामीण कहेंगे तो पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

शुक्रवार को वृहद वृक्षारोपण अभियान की शुरूआत की गई

उन्नाव में विश्व पर्यावरण दिवस और मुख्यमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुक्रवार को वृहद वृक्षारोपण अभियान की शुरूआत की गई। नवाबगंज स्थित वन विभाग परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह सहित कई जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पौधरोपण किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए लोगों से अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री की प्रेरणा और शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इस वर्ष जिले में लाखों पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर तक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में सभी विभागों, ग्राम पंचायतों, स्थानीय निकायों के साथ-साथ किसानों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि इसे जन आंदोलन का स्वरूप दिया जा सके। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका संरक्षण और देखभाल भी अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से प्रत्येक विभाग और ग्राम पंचायत को लगाए गए पौधों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। आगामी वर्षा ऋतु में भी वृक्षारोपण अभियान लगातार जारी रहेगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के "एक पेड़ मां के नाम" अभियान का भी उल्लेख किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि यह अभियान लोगों को भावनात्मक रूप से पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने का प्रभावी माध्यम है। यदि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण करे तो पर्यावरण संतुलन की दिशा में बड़ा बदलाव संभव है।

मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे
आज से शुरू होगा विशेष जनसंपर्क अभियान

लोकसभा चुनाव 2024 के बाद केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपना लगातार तीसरा कार्यकाल शुरू किया, जबकि भाजपा ने केंद्र में शासन के 12 वर्ष पूरे होने का दावा किया है।इसी अवसर पर पार्टी देशभर में अपनी उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए विशेष जनसंपर्क अभियान चला रही है।

केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में भी व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। यह अभियान 5 जून से 21 जून तक चलाया जाएगा। इसके तहत पार्टी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि गांव-गांव तथा शहर-शहर जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। भाजपा प्रदेश नेतृत्व के अनुसार अभियान के दौरान लाभार्थी संपर्क कार्यक्रम, चौपाल, जनसंवाद, प्रेस वार्ता और प्रदर्शनी जैसे आयोजन किए जाएंगे। पार्टी का दावा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में आधारभूत ढांचे, डिजिटल सेवाओं, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। इन्हीं उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए यह विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश भाजपा इकाई ने जिला स्तर पर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली है। केंद्रीय और राज्य स्तर के नेता भी विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क करने और उनकी प्रतिक्रिया लेने की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि विपक्षी दलों ने इस अभियान को राजनीतिक प्रचार करार दिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि सरकार अपनी उपलब्धियों का प्रचार करने के बजाय बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं पर जवाब दे। विपक्ष का आरोप है कि सरकारी संसाधनों का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए यह अभियान काफी महत्वपूर्ण है। पार्टी एक ओर अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना चाहती है, वहीं दूसरी ओर बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने का प्रयास भी कर रही है। ऐसे में यह अभियान आने वाले राजनीतिक माहौल को प्रभावित कर सकता है और प्रदेश की राजनीति में नई बहस को जन्म दे सकता है।

नोएडा के अपार्टमेंट में 12वें फ्लोर पर लगी भीषण आग

नोएडा में शुक्रवार सुबह करीब 7:20 बजे नोएडा के सेक्टर-75 स्थित आईवी कंट्री सोसाइटी में एक हाईराइज रिहायशी बिल्डिंग के 12वें फ्लोर पर भीषण आग लग गई। 28 मंजिला इस बिल्डिंग में आग लगते ही देखते-ही-देखते पूरे फ्लैट में लपटें फैल गईं और खिड़कियों से ऊंची-ऊंची आग की लौ बाहर निकलने लगी। आसमान में घना काला धुआं छा गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। नोएडा सेक्टर-75 की आईवी कंट्री सोसाइटी में 12वीं मंजिल पर लगी आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम की नाकामी पर स्थानीय लोगों ने तेज नाराजगी जताई। जब फायर ब्रिगेड की पाइप से पानी की फुहारें 12वीं मंजिल तक नहीं पहुंच पाईं, तब लोगों ने गुस्से में कहा, "ये फायर ब्रिगेड क्या है, होली के फव्वारे तो ज्यादा बेहतर हैं। 6-7 फ्लोर के ऊपर पानी पहुंच ही नहीं रहा। ये बस नीचे वाले घरों में पानी डाल रहे हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह यूजलेस है।" सोसाइटी के टावर-A के एक फ्लैट में एयर कूलर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग सबसे पहले बालकनी से शुरू हुई और तेजी से पूरे फ्लैट में फैल गई। आग की भयंकर तीव्रता के कारण फ्लैट का सारा सामान जलकर राख हो गया। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने बताया कि सुबह अचानक धुआं और लपटें देखकर वे सीढ़ियों से भागकर नीचे उतरे। कई लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किए, जिसमें लपटें और धुआं साफ दिख रहा है। फायर विभाग और पुलिस की टीमें लगातार मौके पर हैं। आग को पूरी तरह काबू करने और आगे फैलने से रोकने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी, लाखों अभ्यर्थियों की नजर 14 जून पर

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली राजकीय इंटर कॉलेज (GIC) प्रवक्ता भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। आयोग ने परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं और प्रदेश भर के परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 14 जून को आयोजित होने वाली इस परीक्षा में लाखों अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है।यह भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से चर्चा में रही है और प्रदेश के युवाओं को इसका बेसब्री से इंतजार था। आयोग के अनुसार भर्ती अभियान के माध्यम से विभिन्न विषयों के कुल 1,500 से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। परीक्षा के लिए प्रदेश के अनेक जिलों में केंद्र बनाए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है।आयोग ने अभ्यर्थियों को परीक्षा से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। उम्मीदवारों को निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने, प्रवेश पत्र और पहचान पत्र साथ रखने तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को परीक्षा केंद्र में न लाने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है।शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर युवाओं में उत्साह के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा भी काफी अधिक है। कई अभ्यर्थी वर्षों से इसकी तैयारी कर रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि योग्य शिक्षकों की नियुक्ति से सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार होगा और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सकेगा। प्रदेश सरकार भी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे में यह भर्ती अभियान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। परीक्षा के सफल आयोजन के बाद अभ्यर्थियों की निगाहें परिणाम और नियुक्ति प्रक्रिया पर रहेंगी।

चुनाव आयोग से पूछा- आखिर कब होंगे चुनाव?

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों में लगातार हो रही देरी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गुरुवार को कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब मांगते हुए पूछा कि पंचायत चुनाव आखिर कब तक कराए जाएंगे और इसकी संभावित समयसीमा क्या है। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद प्रदेश की राजनीति में पंचायत चुनाव का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है।खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थानीय निकायों का समय पर चुनाव होना आवश्यक है। पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद चुनाव कार्यक्रम घोषित न होना चिंता का विषय है। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को अगली सुनवाई में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।गौरतलब है कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रदेश सरकार ने ग्राम प्रधानों को अस्थायी रूप से प्रशासक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार जानबूझकर चुनाव टाल रही है ताकि स्थानीय स्तर पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखा जा सके। वहीं सरकार का कहना है कि आरक्षण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण चुनाव कार्यक्रम में देरी हुई है।राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीतिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पंचायत स्तर पर मजबूत प्रदर्शन करने वाले दलों को विधानसभा चुनाव में भी लाभ मिलने की संभावना रहती है।हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग पर चुनाव कार्यक्रम घोषित करने का दबाव बढ़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी चुनाव को लेकर उत्सुकता बढ़ रही है। अब सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां चुनाव की संभावित तारीखों को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।